

Regarding utilization of unutilized land acquired for coal mining-laid

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल) : मेरे संसदीय क्षेत्र के शहडोल, उमरिया, अनुपपुर जिलों का बहुत बड़ा भाग कोयला उत्पादन क्षेत्र है। SECL के द्वारा क्षेत्र में बहुत बड़ा भू-भाग समय समय पर अधिग्रहीत किया गया है या लीज पर लिया है। ली गयी ज़मीन में से हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मूलतः इन क्षेत्रों में स्थित नगरो, ग्रामों में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा संचालित अनेक योजनाओं जैसे नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क निर्माण, खेल मैदान, स्कूल, अस्पताल, अनेक प्रकार के सार्वजनिक योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, परिणामस्वरूप मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि कोल इंडिया द्वारा लीज या अधिग्रहीत की गई भूमि जिनका उपयोग नहीं हो रहा है या रिक्त पड़ी है अथवा अधिग्रहीत जमीन जिसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, ऐसी खाली पड़ी जमीन विकास योजनाओं के लिए चाहे वे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उन्हें आवंटित की जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य जो जमीन अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है, वे कार्य तेजी से किए जा सकें।